जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 295 प्रभात हिण्डौन सिटी, शुक्रवार 29 अगस्त, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

हाईकोर्ट ने वो कर दिखाया जो सरकार नहीं कर पाई : एस.आई. भर्ती परीक्षा-2021 रद्द की

हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि एस.आई. भर्ती परीक्षा 2021 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार ही पुनः आयोजित की जाए

- यादवेन्द्र शर्मा -

जयपुर, 28 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यापक पेपर लीक और नकलबाजी के आरोपों को सही मानते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग (आर.पी.एस.सी.) द्वारा एस.आई. भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द कर, महाधिवक्ता की राय के अनुसार 2021 की विज्ञप्ति में संशोधन कर पुनः आयोजित करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार जुलाई 2025 में जारी नई विज्ञप्ति में भी संशोधन कर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर 2021 की भर्तियों को भरने का प्रावधान कर सकती है।

हाईकोर्ट के आदेशानुसार पुनः आयोजित परीक्षा में सभी उम्मीदवारों को आयु सम्बन्धी योग्यता में रियायत दी जाए, साथ ही सभी योग्य अभ्यर्थियों को 2021 में मिल रहे आरक्षण व अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व की सरकारी सेवा का छोड़ा था और फिर एस.आई. भर्ती परीक्षा में चयनित हुए थे, उन्हें पुनः मूल पद पर बहाल किया जाए। अदालत ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने के लिए 8 सितम्बर 2025 तक योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए जाए।

- हाईकोर्ट के आदेशानुसार पुनः आयोजित परीक्षा में सभी उम्मीदवारों को आयु सम्बन्धी योग्यता में रियायत दी जाए, साथ ही सभी योग्य अभ्यर्थियों को 2021 में मिल रहे आरक्षणों व अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जाए।
- अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व की सरकारी सेवा को छोड़ा था और फिर एस.आई. भर्ती परीक्षा में चयनित हुए थे।
- न्यायाधीश समीर जैन ने अपने आदेश में तत्कालीन आर.पी.एस.सी. अध्यक्ष संजय श्रोतिया समेत अन्य सदस्य, जिनमें बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका, मंजू शर्मा, संगीता आर्या और जसवंत राठी पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इन अफसरों ने व्यापक पेपर लीक को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई और आर.पी.एस.सी. की विश्वसनीयता को छलनी किया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश से वो कर दिखाया है जो पिछले डेढ़ वर्ष से राज्य सरकार करने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि, जैसा कि विदित है कि इस मामले में राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एस.ओ.जी.) ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, वी.के. सिंह, की देखरेख में विस्तृत जांच कर रिपोर्ट दायर करी थी कि एस.आई. भर्ती-2021 में अपराधिक गिरोह शामिल थे, जिन्होंने आर.पी.एस.सी. के अध्यक्ष सहित छह सदस्यों के साथ मिलकर व्यापक पेपर लीक के षड़यंत्र को अंजाम दिया था और फिर चयनित अभ्यर्थियों से 'इंटरव्यू' में घूस के लिए अच्छे अंक देने का भी षड़यंत्र रचा था।

बताया जा रहा है कि इस मामले की शुरूआती जांच के दौरान स्वयं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिनेश पटनायक कैनडा में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त

नयी दिल्ली, 28 अगस्त। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी दिनेश के. पटनायक को कैनडा में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि उनके शीघ्र ही पद भार ग्रहण करने की संभावना है।

पटनायक भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं और वह स्पेन में भारत के राजदूत की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

उल्लेखनीय है कि कैनडा में भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री

- दो वर्ष पहले ट्रूडो के शासनकाल में दोनों देशों में भारी तनाव के कारण कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर दिए गए थे।

नरेन्द्र मोदी और कैनडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच गत जून में जी-7 की आउटरीच बैठक के दौरान हुई मुलाकात में संबंधों को सुधारने पर बनी सहमति के बाद की गयी है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने दिल्ली और ओटावा में उच्चायुक्तों की बहाली का निर्णय लिया था।

खालिस्तानी संगठन से जुड़े हरदीप सिंह निज्जर की दो वर्ष पहले हुई हत्या को लेकर जस्टिन ट्रूडो सरकार ने इसमें भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। भारत ने इससे साफ इंकार किया था

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मैंने कभी नहीं कहा मैं 75 साल में रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को हो जाना चाहिए'

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल की आयु में रिटायर होने के विवाद पर यह टिप्पणी की

- संघ प्रमुख भागवत के इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में देखा जा रहा है।
- ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितम्बर को और मोहन भागवत 11 सितम्बर को 75 साल के हो रहे हैं।
- संघ प्रमुख ने आरएसएस के शताब्दी वर्ष के सम्बंध में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह भी कहा कि भाजपा व आरएसएस के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं है। हमें एक-दूसरे पर विश्वास है।

नई दिल्ली, 28 अगस्त। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के 100 साल पूरा होने के मौके पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान मोहन भागवत से जब पूछा गया कि 75 साल के बाद क्या राजनीति से सेवानिवृत हो जाना चाहिए? तो मोहन भागवत ने कहा कि, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा या किसी और को 75 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए।

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आगे कहा कि मैंने यह बात संघ के वरिष्ठ प्रचारक दिवंगत मोरोपंत पिंगलेजी के बयान का हवाला देते हुए उनके विचार रखे थे। मैंने यह नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को रिटायर हो जाना चाहिए। हम जिंदगी में किसी भी समय रिटायर होने के लिए तैयार हैं और संघ हमसे जिस भी समय तक काम कराना चाहेगा, हम संघ के लिए उस समय तक काम करने के लिए भी तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि हमें नौकरी दी जाती है, हम चाहें या न चाहें। अगर मैं 80 साल का हूं और संघ कहता है कि जाओ और शाखा चलाओ, तो मुझे करना ही होगा। संघ जो भी कहता है, हम करते हैं। यह किसी की सेवानिवृत्ति के लिए नहीं है। हम सेवानिवृत्त होने या काम करने के लिए तैयार हैं। जब तक संघ चाहता है।

उन्होंने कहा कि मैं शाखा चलाने में माहिर हूं, भाजपा सरकार चलाने में माहिर है, हम एक-दूसरे को सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम फैसला नहीं करते, अगर हमें फैसला करना होता तो क्या इसमें इतना समय लगता।

भाजपा और आरएसएस के बीच मतभेद के सवाल पर संघ प्रमुख ने कहा कि मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते। हमारे यहां मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे पर विश्वास है...क्या भाजपा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'प्र.मंत्री मोदी की सतही विदेश नीति का देश को नुकसान ही हुआ'

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोप लगाया कि, सरकार की मुस्कान, गले मिलने और ''सेल्फी'' लेने पर आधारित विदेश नीति, देश के हितों की सुरक्षा नहीं कर सकी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 अगस्त। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि सरकार देश की रक्षा करने में विफल रही है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जी.टी.आर.आई.) की रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग एक प्रतिशत जीडीपी पर असर पड़ सकता है और इसका फायदा चीन को मिलेगा।

बुधवार से अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त शुल्क लागू होने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यापार समझौता न कर पाने और देश की रक्षा न कर पाने का आरोप लगाया।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने चेतावनी दी कि टैरिफ की पहली मार में कम से कम10 सेक्टरों को 2.17 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि विदेश नीति के दिखावटी कार्यक्रम, मुस्कानें, गले लगना और सैल्फी, ने राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुँचाया है।

खड़गे ने कहा, ''आपके प्यारे दोस्त ''अबकी बार, ट्रंप सरकार'' ने आज से भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। हमारे किसान, खासकर कपास के किसान, बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आपने कहा था कि आप उनकी रक्षा करने के लिए कोई भी ''निजी कीमत'' चुकाने को तैयार हैं, लेकिन आपने उनके नुकसान को कम करने और आजीविका बचाने के लिए कुछ नहीं किया।''

उन्होंने कहा कि कई निर्यात-आधारित अहम सेक्टर, खासकर एमएसएमई, में बड़े पैमाने पर नौकरियों का नुकसान होगा।

खड़गे ने कहा कि ''भारतीय वस्त्र निर्यात क्षेत्र में लगभग 5 लाख नौकरियों का नुकसान हो सकता है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल हैं।''

उन्होंने बताया कि अगर शुल्क जारी रहा तो रत्न और आभूषण सेक्टर में भी 1,50,000 से 2,00,000 नौकरियों पर खतरा है। उन्होंने कहा, सौराष्ट्र क्षेत्र में हीरे काटने और पॉलिश करने वाले करीब 1,00,000 मजदूरों की नौकरियां अप्रैल से ही जा चुकी हैं, जब अमेरिका ने 10 प्रतिशत बेस टैरिफ लगाया था।

- खड़गे ने इसी संदर्भ में यह भी कहा, कि ''ट्रेड डील'' (व्यापारिक समझौता) नहीं होने से 10 सैक्टरों में ही 2.17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा।
- भारत के ''टैक्सटाइल उद्योग'' में ही 5,00,000 नौकरियां खत्म हो जायेंगी। जैम्स व ज्वैलरी क्षेत्र में 1,50,000 से 2,00,000 नौकरियां कम हो जायेंगी, हीरे की कटिंग व पॉलिशिंग उद्योग में भी एक लाख वर्कर बेरोजगार हो जायेंगे।

जयपुर महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर

नई दिल्ली, 28 अगस्त। राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक (एनएआरआई) 2025 के अनुसार, कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई महिलाओं के लिए देश के सबसे सुरक्षित शहरों के रूप में उभरे हैं, जबकि पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची सबसे निचले स्थान पर हैं।

गुरुवार को जारी राष्ट्रव्यापी सूचकांक में, 31 शहरों की 12,770

- राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट व महिला सुरक्षा सूचकांक 2025, के अनुसार जयपुर के साथ दिल्ली, पटना व कोलकाता महिलाओं के लिए सर्वाधिक असुरक्षित शहर हैं, वहीं, मुम्बई, कोहिमा, इटानगर आइज़ोल और भुवनेश्वर सर्वाधिक सुरक्षित माने गए हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'वैश्विक नेताओं से निजी रिश्ते बनाने की मोदी की नीति के कारण भारत - अमेरिका सम्बंधों में संकट आया है'

एक पूर्व राजनयिक ने इसके साथ यह भी कहा कि मोदी को लगता था अमेरिका ही भारत की ग्रोथ का आधार है, मात्र अमेरिका पर निर्भरता का खामियाजा भुगत रहा है भारत

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 अगस्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा मोदी सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनाए गए कठोर रवैये से उत्साहित होकर, वाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवैरो ने एक बार फिर भारत पर हमला बोलते हुए यह आरोप लगाया है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष ''मोदी की जंग'' है।

मोदी सरकार को अमेरिकी फरमानों के आगे झुकाने की स्पष्ट कोशिश करते हुए नवैरो दिल्ली पर दबाव बना रहे हैं। दिल्ली पर पहले से ही कई मोर्चे से दबाव पड़ रहा है। एच वन-बी वीज़ा कार्यक्रम को लेकर धमकियों से लेकर पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम लागू करने के बार-बार किए जा रहे दावों तक।

अनुभवी विदेश नीति विश्लेषकों का मानना है कि मोदी की अत्यधिक व्यक्तिगत विदेश नीति शैली और विश्व नेताओं से हरेक से एक निजी संबंध बनाने की उनकी इच्छा ने भारत-अमेरिका संबंधों में मौजूदा संकट को जन्म दिया है। एक पूर्व राजनयिक ने बताया कि मोदी और भाजपा इस विश्वास में थे कि अमेरिका भारत की प्रगति की कुंजी है, और इसलिए वॉशिंगटन के साथ रिश्तों पर ही सारा ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन जब सारे उम्मीदें एक पर ही टिका दी जाए, तो खतरा बढ़ जाता है।

ब्लूमबर्ग को बुधवार को दिए इंटरव्यू में नवैरो ने कहा, ''भारत जो कर रहा है, उससे अमेरिका में हर कोई हार रहा है। उपभोक्ता, व्यवसाय, सब को नुकसान हो रहा है। नौकरियां जा रही हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, आमदनी और मजदूरी पर असर पड़ रहा है। और फिर टैक्स देने वालों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें मोदी की जंग के लिए फंड देना पड़ रहा है।''जब उनसे पूछा गया कि क्या वे ''पुतिन की जंग'' कह रहे हैं,

- अमेरिका क्यों हाथ धोकर भारत के पीछे पड़ा है इस पर एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा, रुस से तेल खरीदने का मुद्दा तो बहाना मात्र है असली कारण अर्थव्यवस्था है। अमेरिका भारत के कृषि बाजार में घुसना चाहता है, और भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि यह देश के किसानों के लिए घातक होगा।
- वाइट हाउस के ट्रैज़री सैक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट ने भी इस बात की पुष्टि यह कहकर कर दी, कि विवाद सिर्फ ''रुसी तेल'' के कारण नहीं है। वॉशिंगटन की टैरिफ गन का निशाना तो भारत की ''ट्रेड'' सम्बंधी बाधाएं हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी जापान और चीन यात्रा पर रवाना

नई दिल्ली, 28 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जापान और चीन के पांच दिवसीय दौरे रवाना हो गए। पीएम मोदी के दौरे का मुख्य एजेंडा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करना है। अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच हो रही पीएम मोदी की यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण समझी जा रही है। पीएम मोदी जापान के बाद चीन जाएंगे। जहां वहशंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात कई

- प्र.मंत्री मोदी पहले जापान जाएंगे, जहां वे दो दिन रहेंगे, इसके बाद वे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन की शिखर वार्ता में शामिल होने के लिए चीन जाएंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत ने ट्रंप की ''टैरिफ दादागिरी'' के जवाब में गिड़गिड़ाने की नहीं सामना करने की नीति फाइनल की

इस नीति के तहत भारत कोई अर्ज़ी नहीं देगा कुछ रियायत करने की, और न ही इन्तज़ार करेगा ट्रंप में हृदय परिवर्तन होने का

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 28 अगस्त। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ झटके के प्रति भारत ने झुकने की बजाय खुला विरोध कर सीधे मुकाबला करने का रास्ता चुना है। न तो किसी छूट के लिए याचिका दायर की जाएगी, न ही वॉशिंगटन के रुख में बदलाव का धैर्यपूर्वक इंतजार किया जाएगा। इसके बजाय, नई दिल्ली ने तीन-स्तरीय प्रतिकार रणनीति अपनाई है - अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए निर्यात बाजारों में विविधता लाना, कर सुधारों के माध्यम से घरेलू मांग को प्रोत्साहित करना, और अगली पीढ़ी के नीतिगत परिवर्तनों में तेजी लाना।

- भारत के नीतिकारों का मानना है, ''डॉमैस्टिक कंज़ंप्शन'' (देश की घरेलू डिमान्ड) का आज भी योगदान, जी.डी.पी. के आंकड़े में 61 प्रतिशत है, और कुछ और टैक्स आदि की रियायतें देकर भारत की ''घरेलू डिमान्ड'', को और अधिक बढ़ाने की काफी गुंजाइश (स्कोप) है।
- इसी दिशा में बढ़ते हुए, हाल ही में जी.एस.टी. का सरलीकरण करने की घोषणा की गई है, तथा दो ही ''स्लैब'' (वर्ग), 12 प्रतिशत व 18 प्रतिशत रह जायेंगे।
- भारत का यह इतिहास रहा है कि जब भी विदेशी दवाब पड़ा है, भारत दबाव के आगे झुका नहीं। पं. नेहरु पर भारी दबाव था शीत युद्ध के जमाने में, अमेरिका का खेमा या रुस का खेमा जॉइन करने का, पर, उन्होंने ''नॉन एलाइन्ड'' (निर्गुट) रहने का निर्णय लिया। इंदिरा गांधी भी, 1971 के संकट के समय अमेरिका के दबाव में कतई नहीं आईं तथा 1998 में एन.डी.ए. की सरकार ने ''न्युक्लियर टेस्ट'' करने का फैसला किया, पाश्चात्य देशों द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद।

यह रुख भारत की उस ऐतिहासिक प्रवृत्ति के अनुरूप है जिसमें वह महाशक्तियों के दबाव का प्रतिकार करता आया है। नेहरू द्वारा शीत युद्ध के गुटों में शामिल होने से इनकार करने से लेकर इंदिरा गांधी द्वारा1971 संकट के दौरान विरोध जताने और 1998 में पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद परमाणु परीक्षणों को आगे बढ़ाने तक, यह प्रवृत्ति जानी पहचानी रही है। हर बार, भारत ने बाहरी दबाव को आत्मनिर्भरता जताने और दीर्घकालिक रणनीति को फिर से गढ़ने का अवसर बनाया है।

इसी भावना के तहत, मोदी सरकार इस टैरिफ वृद्धि को कोई गंभीर झटका नहीं बल्कि एक उत्प्रेरक के रूप में ले रही है। अमेरिकी व्यापार आदेशों को बाध्यकारी न मानकर भारत यह संकेत दे रहा है कि वह अल्पकालिक कठिनाइयों को सहने को तैयार है, ताकि एक अधिक लचीली अर्थव्यवस्था बनाई जा सके - जो घरेलू मांग पर आधारित हो और जिसकी वैश्विक साझेदारियों में विविधता हो।

बुधवार से प्रभावी हुए 50 प्रतिशत टैरिफ का असर अमेरिका को होने वाले भारत के 45 अरब डॉलर के निर्यात पर पड़ेगा, जिसमें केवल दवाएं, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दिया गया है। वस्त्र, रत्न, झींगा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों के लिए यह वृद्धि कमजोर होती

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बाढ़

सुकमा, 28 अगस्त। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में लगातार बारिश से उफान पर आई शबरी नदी और नालों के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर गीदम नाला के पास 48 घंटे से फंसी बस में सवार यात्रियों को जिला प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीमों ने नाव की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। इसके साथ ही यात्रियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था भी ष की गई।

जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज़ कर दिए हैं। अब तक जिले के विभिन्न प्रभावित इलाकों में 22 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहाँ

- राष्ट्रीय राजमार्ग पर 48 घंटे से फंसी बस के यात्रियों को बचाया गया। अब तक 2000 नागरिकों का पुनर्वास किया जा चुका है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)